



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2005/भाद्र 22, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005/BHADRA 22, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 सितम्बर, 2005

सं. टीएएमपी/26/2003-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा इसके वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करते हैं।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/26/2003-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

....

आवेदक

आदेश

(अगस्त 2005 के 30वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने तृतीकोरिन पत्तन न्यास के दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ाते हुए हाल ही में 15 मार्च, 2005 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को राजपत्र सं. 43 के माध्यम से 31 मार्च, 2005 को अधिसूचित किया गया था। टीपीटी को सलाह दी गई थी कि वह अपना व्यापक प्रस्ताव अधिक से अधिक 30 जून, 2005 तक अवश्य दाखिल कर दे ताकि दरमान की अगली सामान्य समीक्षा की जा सके।

2. टीपीटी ने सूचित किया है कि दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव, इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले इसके न्यासी मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। किन्तु, टीपीटी के 14वें न्यासी मंडल का गठन अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। अतएव, इसने वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि संशोधित प्रस्ताव, पूरी तरह से गठित न्यासी मंडल के विचारों के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

3. चूंकि यह इसके दरमान की व्यापक समीक्षा है, टीपीटी को उचित लगता है कि प्राधिकरण के समक्ष इसे प्रस्तुत करने से पहले न्यासी मंडल द्वारा उस पर विचार किया जाए। टीपीटी अधिनियम में समाहित प्रशुल्क समायोजन व्यवस्था के अन्तर्गत, इस प्राधिकरण के समक्ष प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए पत्तन के न्यासी मंडल का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, यह प्राधिकरण न्यासी मंडल के विचारों के मूल्य की सराहना करता है। इसी समय, यह प्राधिकरण टीपीटी के प्रशुल्क की समीक्षा में और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी समीक्षा में पहले ही, बहुत विलम्ब हो चुका है। इसलिए, जहाँ टीपीटी का अनुरोध मान लिया गया है वहीं यह प्राधिकरण पत्तन को सलाह देता है कि वह अपना प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 2005 तक या उससे पहले अवश्यमेव प्रस्तुत कर दे। यदि किसी कारण मंडल का तब तक भी पूरी तरह गठन नहीं होता है, पत्तन न्यासी मंडल के विचार अलग से भेज सकता है जिन्हें प्रासंगिक कार्यविवरण में रिकार्ड कर लिया जाएगा।

4. पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/31/2002, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के द्वारा अनुमोदित दरमान की वैधता, जिसमें बाद में पारित विभिन्न आदेशों द्वारा संशोधन किया गया था, 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाई जाती है। टीपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अगली समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रस्तुत कर दे ताकि दरमान की समीक्षा की जा सके। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह प्राधिकरण उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दरमान की समीक्षा अपने आप कर देगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2005/अंसा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th September, 2005

No. TAMP/26/2003-TPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal received from the Tuticorin Port Trust for extension of the validity of its existing Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/26/2003—TPT

Tuticorin Port Trust (TPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 30th day of August, 2005)

This Authority had recently passed an Order on 15th March, 2005 extending the validity of Scale of Rates of Tuticorin Port Trust till 30th September, 2005. This Order was notified on 31st March, 2005 *vide* Gazette number 43. The TPT was advised to file its comprehensive proposal latest by 30th June, 2005 to enable next general review of its Scale of Rates.

2. The TPT has informed that the revised proposal for general revision of its Scale of Rates is to be submitted to its Board of Trustees prior to submission to this Authority; however, the 14th Board of Trustees of the TPT is not yet fully constituted. It has therefore, requested this Authority to extend the validity of existing Scale of Rates for further period till 31st March, 2006 so that revised proposal with the views of fully constituted Board can be submitted.

3. Since it is a comprehensive review of its Scale of Rates, the TPT finds it would be appropriate if its proposal is considered by the Board of Trustees before filing it to this Authority. Under the tariff setting arrangement envisaged in the MPT Act, approval of the Board of Trustees of a Port is not necessary for filing tariff proposal before this Authority. This Authority, however, appreciate the value of the views of the Board of Trustees. At the same time, this Authority also does not like to delay the review of tariff at TPT which is over-due. Hence, while the request of TPT is granted, this Authority advises the port to file its proposal on or before 31st December, 2005 positively. If for some reasons the Board is not fully constituted even then, the port can separately forward the views of the Board of Trustees which will be taken on record in the relevant proceedings.

4. The validity of the existing Scale of Rates approved *vide* its earlier Order Number TAMP/31/2002 dated 20th September, 2002 as amended through various orders passed subsequently is extended upto 31 March, 2006. The TPT is directed to file its comprehensive proposal for next review latest by 31st December, 2005 to enable next general review of its Scale of Rates. In case such a proposal is not received within the specified time, this Authority will proceed with *suo motu* review of the Scale of Rates based on the available information.

A. L. BONGIRWAR, Chairman.

[ADVT-III/IV/143/2005/Ext.]